देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vps/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest मंगलवार, 31 मार्च 2020

भूख के सामने सिस्टम फेल

भूख या कोरोना,किसका भय अधिक?

जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन के लोकडाउन की घोषणा की,ऐसा लगा जैसे पूरा देश कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए वहीं का वहीं ठहर जाएगा|इस लोकडाउन से पहले हुए एक दिन के " जनता कर्फ्यू" की सफलता से हम सभी को विश्वास हुआ कि देश के सभी अनुशासित नागरिक इस लोक डाउन का तन-मन धन से पालन करेंगे और देश कोरोना वायरस के खतरे से बाहर निकल जायेगा|परन्तु घोषणा के अगले ही दिन दिल्ली,गुजरात,महाराष्ट्र से हजारों मजदूरों के पलायन की खबरे आने लगी|टी.वी. खोलते ही दिल्ली के आनंद विहार पर हजारों की भीड़ देख कर माजरा समझ में आने लगा|टी.वी. रिपोर्टरों ने जब इन लोगो से बातचीत की तो लगभग सबका जवाब यही था कि भूखों मरने से अच्छा है कोरोना के खतरे के बावजूद अपने गाँवों तक पहुचना|संभव भी है कि कोरोना का तो पता नहीं परन्तु भूख से इन मजदूरो ने कई अपनों को मरते देखा होगा|स्वयं इन्होने भी बिना मजदूरी के भूखो रहते,महानगरों की ख़ाक छानते हुए राते बितायी होगी|इन लोगो को यकीन था कि गाँव पहुँचने पर यदि कोरोना से मर भी गये तो गाँव के लोग उन्हें जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम तो कर ही देंगे|

पलायन के जिम्मेदार कौन?

सिस्टम:-भले ही लोकडाउन की घोषणा के बाद राज्य सरकारों ने लोगो के रहने का इंतजाम किया हो परन्तु शायद मजदूर वर्ग को सरकारों की कथनी पर यकीन नहीं था,जिसके चलते ही इन लोगो ने मजबूरन पलायन का रास्ता चुना|सिस्टम से इन गरीब मजदूरों का शायद अनेकों बार पहले भी पाला पड़ चूका है जिसके चलते ही इन लोगो को मालूम था कि भले ही एक दिन तो सरकारी लवाजमा दिखावे या दबाव के चलते इनके पास आ सकता है परन्तु रोज रोज नहीं आ पायेगा|हो भी क्यों ना यदि यह सिस्टम आज की तरह, पहले भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सजगता और पूरी संवेदनशीलता से करता तो शायद इन मजदूरों के पलायन की नौबत ही नहीं आती|सरकार की स्वास्थ्य योजना,पेंशन योजना,पी.एफ योजना जैसी सैकड़ों योजनाओं के बावजूद हमारा सरकारी सिस्टम इन लाखों करोड़ों मजदूरों के ना तो स्थायी रोजगार का प्रबंध कर सका है और नाही रोटी कपडा और मकान का|जिसके चलते ही इन मजदूरों को 21 दिन का लोकडाउन मौत के कुँए के जैसा नजर आया,उन्हें मालुम था कि दो-तीन दिन तो भूखे रहकर गुजारा किया जा सकता है परन्तु 21 दिन में यकीनन उनका और उनके परिवार वालों का भूख के चलते मौत से सामना होगा|

सिस्टम की ऐसी ही संवेदनहीनता हमे यू.पी.में देखने को मिली जहाँ पर ऐसे ही कुछ मजदूरों पर सेनेटायीजिंग के नाम पर कीटनाशक का छिडकाव कर दिया गया,वहीँ एक पुलिसकर्मी ने लोकडाउन तोड़ने वाली महिलाओं के माथे पर मार्कर से लिख दिया था कि मैं समाज की दुश्मन हूँ|यह तो एक बानगी है जो मीडिया ने उजागर कर दिए,ऐसे कई मामले तो सामने ही नहीं आ पाते|

जन प्रतिनिधि:-स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने इन लोगो पर ध्यान नहीं दिया क्यूंकि यह महज उनके लिए भीड़ है वोट बैंक नहीं|यदि इन सभी पलायन करने वाले मजदूरों के नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में होते तो यकीनन इन मजदूरों पर हक जताने कई छुटभैये नेताओं के साथ कई बड़े नाम भी जुड़ जाते|अब चूँकि इनके नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में नहीं है इसलिए हमारे प्रिय जन प्रतिनिधि इन पर एक धेले का भी खर्चा नहीं करना चाहते|

उद्योगपति:-जिन फेक्टरियों,कारखानों में यह मजदूर काम करते है उनके लिए यह केवल दिहाड़ी मजदूर है जिन्हें ना तो बीमा,पेंशन पी.एफ. देना पड़ता है और नाही स्थायी रूप से रोटी,कपडा और मकान|इन्होने लोकडाउन के बाद इन मजदूरों को रोकना कतई मुनासिब नहीं समझा क्यूंकि इनको रोकने पर इन मालिकों को सरकार के निर्देशानुसार पैसा देना पड़ता|

फोटो खिंचाऊ जनता/कथित समाजसेवी:-सोशल मिडिया के बढ़ते चलन ने सेवा को भी दिखावा बना दिया है|जिसके चलते ही हमे रोज कई तस्वीरे देखने को मिलती है जिनमे 10-10 व्यक्ति एक आदमी को केला देते दिखाई देते है,शायद इन लोगो को भिखारियों और गरीबों के बीच अंतर भी नजर नहीं आता,जिसका उदाहरण है कि ऐसे लोग दान पुण्य का दिखावा करने के लिए भिखारियों को ही सामान वितरण कर फोटो खिंचा लेते है|यदि ऐसे लोगो पर यकीन कर, व्यवस्थाएं छोड़ दी जाए तो इन गरीब लोगो का भूखों मरना निश्चित है|